

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भारतपुर

अपील संख्या:- 251/17 (RCMS No.2017/00269) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

मीरादेवी पत्नि जगदीश जाति जाटव निवासी ग्राम खरगपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....अपीलान्त

बनाम

1. ग्राम पंचायत भदियाना पंचायत समिति धौलपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भदियाना पं.सं. सैपऊ
2. शिवचरन पुत्र मिहीलाल जाति जाटव निवासी लक्ष्मणपुरी धनौली तहसील व जिला आगरा
..... रैस्प0

अपील विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ दिनांक 20.07.2015 एवं नामा0 सं0 1931 ग्राम पंचायत भदियाना तह0 सैपऊ

उपस्थिति:-

1. श्री दिनेश चन्द शर्मा वकील अपीलान्त
2. श्री पुरुषोत्तम मुदगल वकील रैस्प0

निर्णय दिनांक:-05.07.2018

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के निर्णय दिनांक 20.07.2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 1931 निर्णय दिनांक 05.12.14 ग्राम खरगपुर तहसील सैपऊ द्वारा ग्राम पंचायत भदियाना तहसील सैपऊ के विरुद्ध प्रस्तुत की है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नामान्तरकरण संख्या 1931 ग्राम खरगपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर वयनामा दिनांक 16.10.2014 के आधार पर पटवारी द्वारा शिवचरन पुत्र मिहीलाल के स्थान पर मीरादेवी पत्नि जगदीश जाटव के नाम भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष पेश हुआ। सरपंच ग्राम पंचायत भदियाना ने प्रस्ताव सं0 1 के अनुसार नामान्तरकरण दिनांक 05.02.14 को अस्वीकार कर दिया। इस

आदेश के विरुद्ध मीरादेवी ने उप जिला कलक्टर सैपऊ के न्यायालय में अपील पेश की। उप जिला कलक्टर सैपऊ ने प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि नियमानुसार मौके एवं रिकार्ड की जांच कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। दौराने जांच प्रकरण धारा 175 आरटीए का पाया जाता है तो नियमानुसार राज्यहित में सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें। इस निर्णय के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का कथन है कि सरपंच ग्राम पंचायत भदियाना पंचायत समिति धौलपुर ने नामान्तरकरण संख्या 1931 पर प्रस्ताव संख्या 1 से अस्वीकार लिखते हुए दाखिल खारिज तस्दीक किया है उसमें कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि किस आधार पर नामान्तरकरण खारिज किया है, न ही कब्जे की बाबत ही अंकित किया है कि खरीददार का कब्जा नहीं है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया है। रैस्प0 संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा का बेचान अपीलान्ट के हक में जरिये रजिस्टर्ड वयनामा से किया है। उसमें स्पष्ट अंकित है कि कब्जा व दखल आज भी मौके पर आराजी मुवईया पर खरीददार मजकूर का करा दिया है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय एवं ग्राम पंचायत ने मौका ही नहीं देखा है और न ही मौका रिपोर्ट ही प्राप्त की है। महज कयास के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने से ही निर्णय पारित किया है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि शिवराज सिंह पुत्र पदम सिंह जाति गुर्जर को अनुसूचित जाति की आराजी पर किसी भी नियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, फिर भी तहसीलदार सैपऊ को पुनः जांच के लिये आदेश दिया जाना अवैधानिक है। नामा0 पर पटवारी हल्का व गिरदावर ने रिपोर्ट कर रखी है कि अंकन सही है फिर रिकार्ड की क्या जांच होनी है। वयनामा के आधार पर कब्जा क्रेता को दिया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जावे।

विद्वान वकील रैस्प0 सं0 1 ग्राम पंचायत भदियाना पंचायत समिति धौलपुर का तर्क है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। ग्राम पंचायत ने मौके की जांच करवायी थी। जिसमें ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव सं0 1 में यह निर्णय लिया था कि मौके पर क्रेता का कब्जा नहीं है इसलिये नामा0 दर्ज नहीं किया जावे। इसी आधार पर नामान्तरकरण अस्वीकार किया गया था। उनका यह भी तर्क है कि शिवचरन बिक्रेता ने रामफूल के नाम बेचान का एग्रीमेंट किया था। इसके बाद उसने मीरादेवी को बेचान कर दिया जबकि मीरादेवी को बिक्रय नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में सिविल न्यायालय में दावा विचाराधीन है। जब तक सिविल न्यायालय से कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस अपील पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है किसी अन्य का कब्जा है। इसीलिये ही ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण खारिज किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को जांच कर निर्णय के लिये रिमाण्ड किया है। तहसीलदार द्वारा जांच कर निर्णय किया जाना है। अपील के माध्यम से उन्हें कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपीलान्ट का आराजी पर कब्जा नहीं होने से ग्राम पंचायत जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी ख0 नं0 1008 रकवा 2 बीघा 18विस्वा वॉके ग्राम खरगपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का खातेदार शिवचरन पुत्र मिहीलाल जाति जाटव था। अपीलान्त ने उक्त खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 16.10.2014 विवादित आराजी क्रय की थी। वयनामा में स्पष्ट अंकन किया गया है कि कब्जा व दखल आज ही मौके पर अपने आराजी मुवईया पर खारीदार मजकूर का करा दिया है। इससे स्पष्ट है कि वयनामा के दिन ही बिक्रेता ने क्रेता को कब्जा दे दिया था। इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि विवादित आराजी पर अपीलान्त क्रेता का कब्जा नहीं है। ग्राम पंचायत को वयनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था। जैसाकि 2011 आरबीजे (18) 88 में माननीय राजस्व मण्डल ने सिद्धान्त पारित किया है। माननीय उच्चम न्यायालय राजस्थान ने 2007 आरबीजे (14) 372 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्त का कब्जा नहीं माना जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्त की अपील स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा हर दो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय क्रमशः 05.02.2014 एवं 20.07.2015 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार सैपऊ को निर्देश दिये जाते हैं कि वयनामा के आधार पर नियमानुसार नामान्तरकरण कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official